www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 109 | जौनपुर बुधवार, 03 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

चुनाव हारने पर और हताश हो रहा विपक्ष, जनता सब देख रही

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अभिनेत्री–राजनेता कंगना रनौत ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उन पर जानबूझकर बाधा डालने और लगातार चुनावी झटकों के बाद बढ़ती हताशा का आरोप लगाया है। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बार–बार व्यवधान देखा गया। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वे जितना अधिक हारते हैं, उतना ही अधिक निराश होते हैं। कांग्रेस और बाकी दल हताशा की स्थिति में पहुँच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि व्यवधानों के कारण आज के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सके। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कंगना ने आगे कहा कि आज के लिए निर्धारित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। संसद नहीं चल सकी। इसे दो घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया।ष रानौत ने आगे कहा कि इस तरह का आचरण जनता के सामने विपक्ष की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा रहा है। उन्होंने कहा, ष्पूरा देश देख रहा है, और वे (विपक्ष) जनता की नजरों में खुद को गिरा रहे हैं और चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। वहीं, आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, जहां सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि, दोनों सदनों में एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

ऑपरेशन सिंदूर पर नौसेना प्रमुख ने क्या नया बताया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहायह ऐसा अभियान है जो अभी जारी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 7–8 महीनों से पश्चिमी अरब सागर में भारतीय नौसेना एकदम हावी हो गई है। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी नौसेना डरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों में ही दुबकी हुई थी। ऐडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ ऐसा अभियान है जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है। कुल मिलाकर, पिछले नौसेना दिवस के बाद से हमने लगभग 11,000 जहाज दिवस और 50,000 उड़ान घंटे पूरे किए हैं और यह सिलसिला जारी है। हमने 2008 से अदन की खाड़ी में लगातार एक जहाज तैनात रखा है। जहाज को समुद्री डकैती विरोधी कार्यों के लिए तैनात किया जाता है। आज तक, इसके लिए 138 जहाज तैनात किए गए हैं, और उन्होंने सभी राष्ट्रीयताओं और चालक दल के 3,700 से अधिक व्यापारी जहाजों को सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान की है।

योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 20 पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी। एक 14 नंबर के प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण के लिए भेजा गया है। यह निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति के लिए था। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग करने वाले लोगों को एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी पर छूट दी जाएगी। इसके तहत मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 हजार का लाभ आज दिया गया। 1.5 करोड़ का लाभ पहले दिया जा चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक–एक कपंनी को लाभ मिला। बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए निशुल्क भूमि दी जाएगी। यह योग व आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनेगा। कैबिनेट ने इसे भी मंजूर किया। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि, खेल की अवधि और इसके लिए आने–जाने में लगने वाले समय को भी ड्यूटी माना जाएगा। चंदौली में 4.91 अरब से 29.67 किमी सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा। यह सकलडीहा, चहनियां और सैदपुर होते हुए जनपद को गाजीपुर से जोड़ेगा। काफी समय से इसकी मांग चल रही थी। अब इसे मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की नियमावली पर भी संशोधन किया जाएगा। इसके जाति के आधार पर किसी भी बंदी से भेदभाव नहीं हो सकेगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005 एवं 2014 के तहत स्वीकृत एवं निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्तीकरण एवं क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए नीति को लागू किए।

दुष्प्रचार के साथी समझ नहीं पाएंगे : संबित पात्रा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप सरकारी निगरानी के लिए नहीं है। यह ऐप व्यक्तिगत डेटा, संदेशों या कॉल तक पहुँच नहीं सकता। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना और खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना है। पात्रा ने कहा कि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आप देख रहें हैं कि कल से आज तक का सफर किस प्रकार का रहा है। पात्रा ने कहा कि एक विषय है – जिस प्रकार से संसद के सदस्यों का और पार्लियामेंट की बिल्डिंग अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने अपने बयान से बहुत अपमानित किया है। दूसरा विषय संचार साथी का है, इस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या संचार साथी ऐप सरकारी जासूसी के लिए है? क्या सरकार आपकी जासूसी करना चाहती है? नहीं कृ नहीं कृ नहीं। सरकार किसी की जासूसी नहीं करना चाहती। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुष्प्रचार के साथी हैं, वो संचार साथी को को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, वो फिर भी समझ नहीं पाएंगे। मगर जनता–जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि संचार साथी से सरकार कोई जासूसी नहीं करना चाहती है।

जेल में 30 दिन से ज्यादा रहे मंत्री देंगे इस्तीफा, राजनाथ सिंह का वादा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी विरासत को पुनर्जीवित करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और पटेल के भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। सरदार सभा में बोलते हुए, रक्षा मंत्री ने पार्टी द्वारा 130वें संविधान संशोधन को लागू करने के कदम का हवाला दिया, जिसके तहत 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने पर मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। सभा को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी मंत्री के खिलाफ, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, किसी भी शिकायत की जाँच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरदार वल्लभभाई पटेल की इस इच्छा का स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा ने सम्मान किया है... हमने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का भी निर्णय लिया है। अगर कोई पदधारी व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हम इस कानून को भारत की संसद में पारित कराने का प्रयास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम यहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने आए हैं... कुछ राजनीतिक ताकतें थीं जो चाहती थीं कि सरदार वल्लभभाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएँ।

छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक, जन्मदिन पर जेपी नड्डा के जीवन के अनसुने किस्से

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार 3.0 में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 02 दिसंबर को अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरूआत छात्र राजनीति से की थी। वह छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे हैं। हालांकि जगत प्रकाश नड्डा का राजनीतिक सफर उतार–चढ़ाव भरा रहा है। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर जगत प्रकाश नड्डा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में... बिहार के पटना में 02 दिसंबर 1960 को जगत प्रकाश नड्डा का जन्म हुआ था। शुरूआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। जेपी नड्डा ने अपने सियासी जीवन की शुरूआत छात्र राजनीति से की। वह साल 1983–84 में जेपी नड्डा राजनीति में सक्रिय हुए। छात्र राजनीति के बाद जेपी नड्डा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर भाजपा में काम करना शुरूकर दिया। साल 1993 में भाजपा की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बेहद खराब थी। तब केंद्रीय नेतृत्व ने जेपी नड्डा को चुनाव लड़ने के लिए वापस हिमाचल भेजा। इस दौरान भाजपा के सिर्फ 8 सदस्य ही जीतकर विधानसभा पहुंच सके। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनीं। भाजपा के टिकट पर वरिष्ठ नेता जगदेव चंद के साथ युवा नेता जेपी नड्डा भी जुटे। लेकिन शपथ से पहले जगदेव चंद का निधन हो गया। जिसके बाद भाजपा विधायक दल का नेता जेपी नड्डा को चुना गया। ऐसे में जेपी नड्डा नए सिरे से हिमाचल की राजनीति में चर्चा में आए। साल 1993 से लेकर 1998 तक नड्डा ने भाजपा विधायक दल को विधानसभा में चलाया। वहीं साल 2003 में नड्डा मंत्री रहते हुए कांग्रेस के तिलक राज से चुनाव हार गए। फिर साल 2007 में उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन हिमाचल में अपने नेताओं से अनबन के कारण नड्डा केंद्र की राजनीति में चले गए।

9 बार के विधायक प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर, विपक्ष का भी मिला समर्थन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रेम कुमार सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें विपक्षी विधायकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। प्रेम कुमार ने कल इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। वे इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, इसलिए उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा था। विजय कुमार सिन्हा और नंदकिशोर यादव के बाद, प्रेम कुमार भाजपा कोटे से तीसरे अध्यक्ष बने हैं। उनसे पहले, जदयू के दो नेता उदय नारायण चौधरी और विजय कुमार चौधरी अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। प्रेम कुमार के निर्वाचन पर उन्हें बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पूरे सदन की ओर से प्रेम कुमार जी को बधाई देता हूँ। उनके पास लंबा अनुभव है और वे सदन के संचालन में पूरा सहयोग करेंगे। मेरा अनुरोध है कि पूरा सदन एक बार खड़ा होकर उन्हें सम्मान दे। हालाँकि, 74 वर्षीय जदयू प्रमुख ने कुछ विपक्षी नेताओं को धीरे से डाँटा, जो बैठे रहे और जब वे अंततः खड़े हुए तो मुस्कुराए। अपने भाषण में, तेजस्वी यादव ने बताया कि अध्यक्ष जी एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थल शामिल हैं। राजद नेता ने कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्ष सरकार के लिए एक आईने का काम करता है, जिसे शायद हमेशा अपनी कमियाँ नजर न आएँ। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सत्ता पक्ष से भी ज्यादा हमें शामिल करेंगे। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वे उनके सहयोग की आशा करते हैं। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने से पहले, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा के सुचारू संचालन के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव जरूरी है और कहा कि चुनाव 4 दिसंबर को होगा। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है।

खड़गे का हल्ला बोल, नेशनल हेराल्ड मामले में आया नया मोड़

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को 12 साल पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी सरकार और ईडी ने नए आरोपों का इस्तेमाल किया है और विरोधियों को निशाना बनाने के लिए चुनिंदा अभियोजन और नए सिरे से आरोप लगाने का सहारा लिया है। एक्स पर एक पोस्ट में, खड़गे ने लिखा कि 12 साल बाद और अचानक गांधी परिवार पर पुराने मामले में कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाली एक नई एफआईआर। सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए आरोपों का भंडार खत्म हो गया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि जब तथ्य कमजोर पड़ गए, तो नाटकीयता का सहारा लिया गयारू चुनिंदा अभियोजन, बार–बार लगाए गए आरोप, और विरोधियों को कठघरे में खड़ा करने की एक छिपी हुई कोशिश। खड़गे ने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायपालिका इस कदम के पीछे छिपे कथित राजनीतिक मकसद को पहचान लेगी। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न की नासमझ कोशिशों को समझ लेगी! इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने या न लेने के फैसले को फिर से स्थगित कर दिया। आरोपपत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं।

संचार साथी निगरानी का साधन नहीं, जनभागीदारी पर आधारित नागरिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म है : सिंधिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संचार साथी ऐप को लेकर उत्पन्न सभी भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया कि यह ऐप पूरी तरह लोकतांत्रिक, स्वैच्छिक और ग्राहक–केंद्रित है। नागरिक इसे अपनी सुविधा के अनुसार सक्रिय कर सकते हैं और चाहे तो किसी भी समय ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। संचार साथी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो हर मोबाइल यूजर को सशक्त, सुरक्षित और जागरूक बनाता है। यह निगरानी का माध्यम नहीं, बल्कि जनभागीदारी पर आधारित एक पारदर्शी डिजिटल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया कि यह ऐप और पोर्टल नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा, फर्जी कनेक्शनों की पहचान, खोए–चोरी हुए फोन की ट्रैकिंग और साइबर ठगी से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्षम बनाता है। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि ऐप के कॉल लॉग फीचर के माध्यम से किसी भी संदिग्ध नंबर की शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिससे नागरिक स्वयं और दूसरों को संभावित धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। सिंधिया ने कहा डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संचार साथी पूरी तरह स्वैच्छिक, उपयोगकर्ता–केंद्रित और पारदर्शी है, जो भारत के मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है, बिना उनकी निजता से किसी भी तरह का समझौता किए।

चुनाव में हार का गुस्सा संसद में निकाल रहा विपक्ष : रिजिजू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है, इसके चलते बीते दो दिनों में सदन की कार्यवाही भी सुचारू रूप से नहीं चल सकी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। अब सरकार ने कहा है कि वे एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा की समयसीमा तय नहीं कर सकता। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिए थे, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। मंगलवार को राज्यसभा में हंगामे के बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा श्लोग मर रहे हैं, इसके बावजूद एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए।श खरगे ने कहा कि श्मैं चाहता हूं कि इस पर अभी चर्चा हो। यह नागरिकों, देश और लोकतंत्र के हित में है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह इसे लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए विपक्ष समयसीमा तय नहीं कर सकता। रिजिजू ने कहा, श्संसदीय लोकतंत्र में हमें चर्चा करनी चाहिए। देश में कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन आप एक मुद्दे के लिए बाकी को कमतर नहीं आंक सकते। सभी मुद्दे अहम हैं। हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पहले सलाह मशविरा तो करना चाहिए। आप तो समयसीमा तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को अभी बताना चाहिए, ये ठीक नहीं है।श विपक्ष पर तंज कसते हुए रिजिजू ने कहा, श्आप चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, लोगों को आप पर विश्वास नहीं है और अपना गुस्सा संसद में निकाल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। लोकसभा में हंगामे और लगातार हो रहे व्यवधान से बिफरे स्पीकर ओम बिरला ने भी गतिरोध दूर करने के लिए आज तीन बजे सांसदों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि स्थगन प्रस्ताव देने वाले सांसदों के नाम भी नहीं पढ़े जा रहे हैं और प्रस्ताव को खारिज कर दिया जा रहा है। खरगे ने इसे गलत बताया। खरगे ने सभापति के विपक्ष की तरफ न देखने पर भी आपत्ति जताई।

संपादकीय

बीएलओ पर काम का बोझ

बिहार में हुए एसआईआर के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में सुधार के कई निर्देश दिए। अब 12 राज्यों में जारी एसआईआर में उन उपायों को लागू किया गया है। इससे बीएलओज पर काम का बोझ बढ़ गया है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच कई बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) की मौत ने पहले से ही विवादित इस प्रक्रिया में नया आयाम जोड़ दिया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से शांतिमुनी एक्का नाम की एक बीएलओ के आत्महत्या करने की खबर आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर कार्य के दौरान अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा ष्काम के अत्यधिक दबाव, भय एवं अनिश्चितताष के कारण हुआ है और इसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, जिसने ष्अनियोजितष ढंग से यह काम थोप दिया। इसके पहले केरल और राजस्थान से भी एक–एक बीएलओ की मृत्यु की खबर आ चुकी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बिहार में हुए एसआईआर के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में सुधार के कई निर्देश दिए। अब 12 राज्यों में जारी एसआईआर में उन उपायों को लागू किया गया है। इससे बीएलओज पर सत्यापन तथा उसके बाद डेटा को डिजिटल करने का बोझ बढ़ गया है। दूर–दराज के इलाकों में नेटवर्क की कमजोरी तथा गरीबों की बस्तियों में दस्तावेजों की जांच यातनादायक प्रक्रिया बन गई है। इन सभी कार्यों के लिए समयसीमा तय है। मगर व्यावहारिक दिक्कतों के कारण इसे पूरा करना कई जगहों पर मुश्किल साबित हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर के पहले चरण का आधा समय पूरा होने के बावजूद बुधवार तक सिर्फ 16 प्रतिशत फॉर्म्स को डिजिटल किया जा सका। उत्तर प्रदेश में तो यह संख्या चार प्रतिशत भी कम थी। इसलिए इस आरोप में दम है कि निर्वाचन आयोग ने व्यावहारिक नजरिया नहीं अपनाया। उसने जल्दबाजी में और बिना सभी पक्षों को भरोसे में लिए यह महति कार्य शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि श्पहले जिस प्रक्रिया को पूरा करने में तीन साल लगे थे, अब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए आयोग ने बीएलओज पर अमानवीय बोझ डाल दिया है।य मुमकिन है कि इस बयान को राजनीति से प्रेरित माना जाए। मगर निर्वाचन आयोग ने व्यावहारिक दृष्टि नहीं अपनाई, यह धारणा मजबूत होती जा रही है।

संसद को बाधित करना राष्ट्र को बाधित करना है

ललित

भारत की संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से आरंभ हो रहा है और इसके प्रारंभ होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई के हंगामेदार होने का संकेत देने में देर नहीं लगाई। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह एस.आई.आर. सहित कई मुद्दों पर जोरदार ढंग से सदन में अपनी आवाज उठाएगा। विपक्ष संसद में सवाल उठाए, आवाज उठाए, यह उसका संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या यह अधिकार सार्थक बहस के रूप में सामने आएगा या एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़कर भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करेगा। मॉनसून सेशन अगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम था, तो इस बार बहस के केंद्र में एस.आई. आर. है। लेकिन, सरकार और विपक्ष–दोनों से ही सदन के भीतर ज्यादा समझदारी, संयम, शालीनता और सहयोग की अपेक्षा है, ताकि सत्र में अधिक काम हो सके। शीतकालीन क19 दिसंबर तक चलना है। इसमें कुल 15 दिन कार्यवाही चलेगी और इस दौरान शिक्षा, सड़क और कॉरपोरेट लॉ संबंधी कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इसी सत्र में हेल्थ सिक्यॉरिटी एंड नैशनल सिक्यॉरिटी सेस बिल, 2025 भी रखा जा सकता है, जिसका मकसद देश के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तैयारियों के लिए एक नया उपकर लगाना है। सारे ही बिल–प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं और इन पर सार्थक बहस की जरूरत है। निश्चित दौर पर पिछले अनेक वर्षों से संसद की कार्रवाई हंगामे, शोर–शराबे, नारेबाजी की भेंट चढ़ती रही है। पिछला सत्र इस संदर्भ में बेहद निराशाजनक रहा। वेल में आकर नारेबाजी, कुर्सियां ठोकने, प्लेकार्ड दिखाने और लगातार स्थगन जैसे दृश्य दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर पेश करते रहे। वह सत्र देश के संसदीय इतिहास के सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले सत्रों में गिना गया, जब लोकसभा की प्रॉडक्टिविटी महज 31 प्रतिशत के आसपास और राज्यसभा की लगभग 39 प्रतिशत रही। हंगामे और शोर–शराबे की वजह से दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण घंटे बर्बाद हो गए थे। सवाल यह है कि आखिर यह परंपरा कब बदलेगी? कब हमारे जनप्रतिनिधि समझेंगे कि संसद का एक–एक मिनट देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई से चलता है? एक मिनट का व्यर्थ खर्च लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाता है। संसद केवल बहस का मंच नहीं बल्कि देश की नीतियों, कानूनों और विकास–दिशा को तय करने वाला सर्वोच्च स्थल है। लोकतंत्र की सफलता का मूलमंत्र जनता द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों की सजगता, जवाबदेही और गरिमा है। इसलिए संसद का हर क्षण अर्थपूर्ण, कार्यकारी होना चाहिए, हर चर्चा राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए और हर बहस शालीनता तथा परिपक्वता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सत्र को सुचारुरूप से चलाने के लिये सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक आयोजित करना एक स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण परम्परा एवं एक आशा की किरण है। इस बार भी सत्र शुरू होने से पहले 36 दलों का एक साथ बैठक करना एक अच्छी शुरुआत है। यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संवाद और सहयोग की दिशा में एक सार्थक पहल है। देश यह उम्मीद कर सकता है कि यदि सदन का संचालन भी इसी सकारात्मक भावभूमि पर हुआ तो यह सत्र एक आदर्श परंपरा स्थापित कर सकता है। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु मनभेद अनिवार्य नहीं। संसद उन मनभेदों को संवाद में बदलने का पवित्र स्थान है। निश्चित ही विपक्ष की भी अपनी मांगें हैं, जिसे सर्वदलीय बैठक में रखा गया। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, एसआईआर, वायु प्रदूषण और विदेश नीति पर विस्तृत चर्चा चाहता है। अच्छी बात है कि विपक्षी दलों ने इस बारे में पहले ही अवगत करा दिया है और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के ही मुताबिक, किसी ने भी यह नहीं कहा कि संसद नहीं चलने दी जाएगी। सरकार और विपक्ष, दोनों का इस पर सहमत होना कि सदन चलना चाहिए, स्वागत योग्य है। इस सत्र से सरकार 14 महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों को पारित करवाना मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैय यह विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है कि वह रचनात्मक सुझाव दे, आवश्यक संशोधन का आग्रह करे और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए संवाद के माध्यम से कानूनों को दिशा दे। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों दो पहिये हैं, एक पहिया चिटक जाए तो रथ आगे नहीं बढ़ता। आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद में एक नई लकीर खींची जाए–शालीनता की, संवैधानिक मर्यादाओं की, तर्कसंगत बहस की और राष्ट्रीय हित की। दुनिया भर के लोकतंत्रों में बहसें गरम होती हैं, लेकिन गरिमा नहीं टूटती। भारत में भी यह संस्कृति विकसित होनी चाहिए। विपक्ष का काम सरकार को कठघरे में खड़ा करना है, लेकिन वह हंगामे से नहीं बल्कि तथ्यपूर्ण तर्कों से हो। सवाल उठाने का अधिकार तभी सार्थक है जब उसके साथ उत्तर सुनने की तैयारी भी हो। पिछले कुछ सत्रों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि

विपक्ष प्रश्न पूछता है लेकिन उत्तर सुनने का अवसर ही नहीं देता। यह लोकतंत्र की आत्मा का हनन है। संसद सिर्फ आवाज बुलंद करने का मंच नहीं, वह सुनने, समझने और समाधान खोजने का माध्यम है। दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में यह मंच पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाइयों का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को भी विपक्ष के सवालों का सम्मानपूर्वक जवाब देना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी यह समझना होगा कि राजनीति निरंतर संघर्ष का नाम नहीं बल्कि संवाद की प्रक्रिया है। देश की जनता बेहद उम्मीदों के साथ इस सत्र को देख रही है। महंगाई, रोजगार, सुरक्षा, विदेश नीति, सामाजिक सौहार्द, अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा और न्याय–ये सभी गंभीर मुद्दे हैं। जनता चाहती है कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि इन मुद्दों पर ठोस बहस करें। यदि संसद हंगामों का अखाड़ा बन जाए, तो इन मुद्दों का समाधान कैसे निकलेगा? लोकतंत्र का वास्तविक मूल्य कानून में नहीं बल्कि उसके निर्बाध संचालन में हैय यदि संचालन त्रुटिपूर्ण हो जाए, तो कानून भी अर्थहीन हो जाता है। संसद की गरिमा देश की गरिमा है। सांसद केवल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा के वाहक हैं। उनकी भाषा, उनका आचरण और उनकी बहसें भविष्य की राजनीति का मार्ग तय करती हैं। यह चिंता का विषय है कि आज युवा पीढ़ी संसद के व्यवहार को लोकतंत्र का आदर्श नहीं, बल्कि अव्यवस्था का प्रतीक मानने लगी है। सदन की मर्यादा केवल स्पीकर या सभापति पर निर्भर नहीं, बल्कि सभी सांसदों के संयम एवं शालीनता पर निर्भर है। सभापति का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, विषय पर रहने वाली बहस करना और असहमति में भी सभ्यता–शालीनता बनाए रखना–ये संसदीय चरित्र के मूल तत्व हैं। इनका पालन ही संसद की शुचिता को बनाए रख सकता है। यदि सरकार बहुमत के अहंकार में विपक्ष की उपेक्षा करती है तो यह गलत हैय लेकिन यदि विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका छोड़कर केवल अवरोध बन जाए तो यह भी लोकतंत्र के साथ अन्याय है। संसद तभी सफल होगी जब दोनों तरफ का आचरण सकारात्मक हो। इस दृष्टि से शीतकालीन सत्र नई परंपराओं का प्रारंभ बनना ही चाहिए। इस बार के सत्र से यह अपेक्षा है कि यह एक सकारात्मक, शालीन और प्रगति का सत्र बने। यह केवल कानून पारित करने का सत्र न होय यह संवाद का, सौहार्दपूर्ण वार्ता का, समस्याओं के समाधान का और राष्ट्रीय हित के नए संकल्प का सत्र हो। यदि इस बार पक्ष और विपक्ष मिलकर अनुशासन, मर्यादा और जिम्मेदारी की एक नई लकीर खींच दें, तो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह सत्र मील का पत्थर बन सकता है। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए प्रेरणा बन सकता है, बशर्ते संसद स्वयं अपने भीतर अनुशासन, शांति और संवाद की संस्कृति को स्थापित करे। यह सत्र उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। देश आज यही उम्मीद कर रहा है कि जो सर्वदलीय बैठक शांति और सहमति से हुई, उसी भाव के साथ संसद का संचालन भी हो। यदि यह संभव हुआ तो यह केवल एक सत्र की सफलता नहीं होगी, बल्कि भारत के लोकतंत्र की विजय होगी।

विपक्ष के लिए गहरे आत्म–मंथन का विषय

सत्येन्द्र रंजन

अब भविष्य सिर्फ उन शक्तियों का है, जो राजनीति की नई समझ और परिभाषा अपना सकें। जो राजनीति की ऐसी समझ अपना सकें, जिसमें चुनाव लड़ना ही एकमात्र गतिविधि ना हो। जिसमें उद्देश्य आधारित संगठन, संघर्ष, और रचनात्मक कार्यक्रम समान रूप से महत्त्वपूर्ण हों। दरअसल, ऐसी राजनीति जो करेगा, दीर्घकाल में उसके लिए ऐसा जन समर्थन अपने–आप तैयार होगा, जिससे उसे चुनावी सफलता मिले। किसी राज्य में चुनाव हो, तो इस दौर में वहां मंच सज्जा में कई समान पहलू मौजूद रहते हैं और ऐसा बिहार में भी था। बाकी बातें स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों से तय होती हैं, हालांकि उनमें भी कुछ समानताएं ढूंढी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में जो चुनाव नतीजा सामने आया, वह पहले से जारी ट्रेंड के काफी कुछ अनुरूप है। साथ ही इन नतीजों ने उस रुझान को और आगे बढ़ाने में अपने तईं कुछ खास योगदान किया है। ये रुझान भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान एवं भविष्य के बारे में कुछ ठोस संकेत देते हैं– आइए, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। मंच के नेपथ्य में जो बातें आज हर जगह मौजूद रहती हैं, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है चुनाव प्रणाली को लेकर पैदा हुए संदेह। बिहार का चुनाव आते–आते यह पहलू अत्यधिक गंभीर हो गया। इसमें बड़ा योगदान इस चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्द्ढक्र) कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले का रहा। कई ऐसे कारण हैं, जो सघन होकर अब चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर संदेह का साया डाल रहे हैं। उनमें प्रमुख है। मतदाता सूची, जिसमें शामिल और निकाले गए नामों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मतदान के दिन आखिरी घंटों में असामान्य रूप से अधिक मतदान की शिकायत लगातार आ रही है। कई जगहों पर कुछ, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के मतदान की राह में जानबूझ कर रुकावट खड़ा करने की कथित कोशिशों के इल्जाम लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर की चर्चाएं हर बार गर्म होती हैं। विपक्ष की मांग के मुताबिक वीवीपैट पर्चियों की गिनती ना करने के निर्वाचन आयोग के फैसले से विपक्षी खेमों में यह संदेह और गहराया है। मतगणना के दौरान जहां हार–जीत का अंतर कम हो, वहां प्रशासनिक हेरफेर से परिणाम को प्रभावित करने के आरोप कई चुनावों में लगे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे संगीन आरोप लगाए थे। बाद में उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले चर्चित हुए। चुनाव कार्यक्रम तय करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध होती गई है। विपक्षी दलों का इल्जाम है कि चुनाव कार्यक्रम केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सुविधा से तय किए जाते हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने में कथित भेदभाव की शिकायतें आती हैं। ऐसे मामले चर्चित हुए हैं, जब एक जैसे मामलों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर आचार संहिता लागू में निर्वाचन आयोग ने अलग पैमाने अपनाए। निर्वाचन आयोग का भेदभाव बिहार के ताजा चुनाव में एक अलग मुकाम पर पहुंचा, जब महिलाओं के खाते में दस हजार रुपये ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चुनाव के दौरान भी चलती रही। पहले कई चुनावों में निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू होने के दौरान ऐसी योजनाओं के अमल पर रोक लगा दी थी, लेकिन बिहार में इसे पहले से चल रही योजना बता कर जारी रहने दिया गया। ये वो बातें हैं, जो मंच पर घटती दिखती हैं। लेकिन पृष्ठभूमि में कम–से–कम दो और पहलू हैं, जिनसे चुनावी मुकाबले का धरालत सत्ता पक्ष के हक में झुकता चला गया है। इनमें एक तो उसके पास धन की अकूत उपलब्धता है, जो पूंजीपति वर्ग के समर्थन से उसे प्राप्त हुआ है। दूसरी बात का संबंध भी इस वर्ग के समर्थन से जुड़ा है। चूंकि मेनस्ट्रीम मीडिया का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में ही है, इसलिए मीडिया का अनवरत समर्थन सत्ता पक्ष को मिला रहता है। शिकायत है कि चुनाव हों या नहीं, हर वक्त मेनस्ट्रीम मीडिया सत्ता पक्ष के नजरिए से नैरेटिव प्रचारित करने में जुटा रहता है। फिर सोशल मीडिया पर भी सत्ता पक्ष का बेहिसाब प्रभाव है। इन तमाम वो पहलू हैं, जिनकी वजह से भारत में चुनावी धरालत समान नहीं रह गया है। चुनाव कोई भी हो, उसमें ये धरातल भाजपा के पक्ष में पहले से झुका रहता है। उस धरातल पर जब दूसरी पार्टियां मुकाबले के लिए उतरती हैं, तो उनके सामने एक और चुनौती सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बने माहौल से निपटने की होती है। यह ध्रुवीकरण नफरत भरी सांप्रदायिक ध्वनियों के लगातार गूंजते रहने से बनी हुई है। भाजपा और उसके साथी संगठन चुनावों के वक्त पर इन ध्वनियों का वॉल्यूम कुछ और तेज कर देते हैं। एक समय विपक्षी पार्टियों को लगता था कि जातीय ध्रुवीकरण से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुकाबला कर लेंगी। लेकिन अब उनका यह हथियार भी भोथरा हो चुका है। इसकी वजह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघध भाजपा की कथित सोशल इंजीनियरिंग है, जिसके तहत उन्होंने बहुजन, ओबीसी या दलित पहचान को खंडित कर दिया है।

असरदार सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पर जोर देता है भारत पर आईएमएफ का दस्तावेज

अंजन

आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कामकाज में अच्छाई देखी है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत ज्यादा ऊंचे टैरिफ स्तर के बुरे असर को असरदार तरीके से झेला है। अमेरिका को भारत के निर्यात पर 50प्रतिशत टैरिफ के बावजूद, भारत खुशी–खुशी 6प्रतिशत से ऊपर की दर से बढ़ता रहा है। यह किसी भी हिसाब से अच्छा कार्य निष्पादन है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की भारत के साथ ताजा देश स्तरीय विचार–विमर्श के बाद किये गये आकलन से भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत की अच्छी तस्वीर सामने आई है। आईएमएफ के कार्यपालक निदेशकों ने भारत सरकार को अपनी सलाह–मशविरा रिपोर्ट सौंपी है, और साथ ही सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के प्रबंधकों के लिए अपनी सिफारिशें भी दी हैं। आईएमएफ की समीक्षा और सिफारिशों से दो बातें सामने आई हैं जिन पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। पहली, आईएमएफ ने वित्तीय हालत के लिए सरकार की योजना पर ध्यान दिया है, लेकिन खर्च की मॉनिटरिंग और पुनर्समीक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया है। दूसरी बात, यह देखते हुए कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र मजबूत और आम तौर पर स्थिर है, उसने एक ऐसे क्षेत्र का भी जिक्र किया है जहां कमजोरी है। वह है बड़े और बढ़ते नॉन–बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की गंभीर कमजोरियां। आईएमएफ रिपोर्ट बताती हैरू शनिदेशकों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत रही है, जिसे मजबूत पूंजी और नकद स्थिति का सहयोग मिला है।श लेकिन, आईएमएफ के अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अधिकारियों से कहा कि, श्वे नॉन–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बीच कमजोरियों को कम करें और उनकी सघनता और बढ़ते वित्तीय क्षेत्र के आपस में जुड़े होने से होने वाले जोखिम पर सावधानी से नजर रखें। नॉन–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के आपस में जुड़े होने की हाल की कुछ घटनाएं इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत को दिखाती हैं। सरकार के खर्च पर सावधानी बरतने की सलाह एक अच्छी सलाह लगती है। खर्च पर नियंत्रण और सार्वजनिक खर्च से मिलने वाली आय और गुणवत्ता की निगरानी, सरकारी वित्त के प्रबंधन का एक जरूरी पहलू है।सरकार की वित्तीय मजबूती की योजना की तारीफ करते हुए, आईएमएफ के निदेशकों ने सुझाव दिया है कि शवित्तीय घाटे के लक्ष्य को पाने के लिए खर्च पर मजबूत अनुशासन की जरूरत होगी।श यह एक आम सच है। किसी व्यक्ति की जेब में एक रुपया सरकार के खजाने की तुलना में कहीं ज्यादा उत्पादक होता है और कहीं ज्यादा सावधानी से खर्च किया जाता है। हमेशा की तरह, उन्होंने लगातार मजबूत आर्थिक विकास दर और 2047 तक देश को विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा दिलाने के मकसद को पाने के लिए एक जरूरी नीतिगत पहल के तौर पर और श्ढांचागत सुधारश पर जोर दिया है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया हैरू श्आगे देखते हुए, भारत की एक विकसित अर्थव्यस्था बनने की इच्छा को बड़े ढांचागत सुधार को आगे बढ़ाकर सपोर्ट किया जा सकता है जो ज्यादा संभावित आर्थिक विकास को मुमकिन बनाते हैं।श्आईएमएफ ने सुधार के उपायों के पैकेज को बताने के मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिवाय वित्तीय मजबूती के मकसद को जारी रखने और जीएसटी और आय कर की दरों में कमी के कुल सरकारी राजस्व पर असर पर नजर रखने जैसी आम बातों के।आजकल आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ना उसके पहले के नीतिगत पुलिंदे के रुख से काफी अलग है। उदाहरण के लिए, आईएमएफ ने सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पर जोर दिया है, जो पहले उसके लिए एक अभिशाप हुआ करता था। इसने विदेशी मुद्रा बाजार में श्अव्यवस्थितश हालात और सट्टेबाजी को रोकने के इरादे पर भी जोर दिया है। एक समय था जब विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थिरता लाने के लिए दखल देने का आईएमएफ के अर्थशास्त्री मजाक उड़ाते थे। आखिर ये फ्री मार्केट के कामकाज में दखल थे, और आखिर, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार सभी फ्री मार्केट का पवित्र प्याला था। खैर, इन सोच या तय बातों को छोड़ दें, तो कुल मिलाकर आईएमएफ की समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ खास ताकतों को सामने लाती है, जैसा कि आईएमएफ के कार्यपालक निदेशकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। सबसे जरूरी और खास बात यह है कि आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कामकाज में अच्छाई देखी है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत ज्यादा ऊंचे टैरिफ स्तर के बुरे असर को असरदार तरीके से झेला है। अमेरिका को भारत के निर्यात पर 50प्रतिशत टैरिफ के बावजूद, भारत खुशी–खुशी 6प्रतिशत से ऊपर की दर से बढ़ता रहा है। यह किसी भी हिसाब से अच्छा कार्य निष्पादन है। भारत के आर्थिक विकास की दर अच्छी बनी हुई है, जबकि कीमतें स्थिर रही हैं और कुछ कमी भी देखी गई है। आईएमएफ की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2024–25 में 6.5प्रतिशत थी जबकि 2025–26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8प्रतिशत बढ़ेगी। खाने की चीजों की कम कीमतों की वजह से महंगाई की सुर्खियों में तेजी से गिरावट आई। आईएमएफ को उम्मीद है कि इस साल के अच्छे मानसून और तेल की गिरती कीमतों की वजह से महंगाई का स्तर स्थिर रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कीमतों में स्थिरता लगातार खुशहाली का एक जरूरी हिस्सा है, खासकर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में। बेशक, जीएसटी के पुनर्समायोजन से कीमतों को और नियंत्रित रखने में मदद मिलती। हालांकि, यह फैक्टर अगले साल हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा और लगातार ग्रामीण मांग से बढ़ने वाली नई मांग से कीमतें बढ़ सकती हैं।हालांकि, लगातार वैश्विक आर्थिक उथल–पुथल और अनिश्चित व्यापार संभावनाओं को देखते हुए, आर्थिक विकास के घरेलू संचालक ज्यादा अहमियत रखते हैं। मजबूत घरेलू मांग, खासकर ग्रामीण उपभोक्ता मांग, बिना किसी शक के आर्थिक विकास दर को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। इसकी कुंजी मजबूत घरेलू मांग लगती है, जिससे कुल आर्थिक विकास दर को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलनी चाहिए। यह यही मुख्य कारण है कि घरेलू कॉर्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र में तेजी बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन और संभावनाओं का आकलन करने के लिए, आईएमएफ ने कुछ साफ मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। एक श्अच्छेश कारक के तौर पर, फंड के अर्थशास्त्रियों ने निर्यात बढ़ाने के लिए तेजी से ट्रेड डील करने की अहमियत पर जोर दिया है। आईएमएफ ने जोर देकर कहा, श्नकारात्मक पहलू यह है कि वैश्विक आर्थिक बंटवारे के और गहराने से वित्तीय हालात और मुश्किल हो सकते हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है, और व्यापार, एफडीआई और आर्थिक विकास दर कम हो सकती है।श घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, आईएमएफ ने साफ बातों पर जोर दिया हैरू श्मौसम के अचानक झटके फसल की पैदावार पर असर डाल सकते हैं, ग्रामीण खपत पर बुरा असर डाल सकते हैं और महंगाई का दबाव फिर से बढ़ा सकते हैं।

कांग्रेस का एकमात्र मकसद सत्ता प्राप्त करना

बलबीर पुंज

कांग्रेस कभी औपनिवेशिक विभाजनकारी नीतियों से लड़ने का प्रतीक थी। किंतु दुर्भाग्य से, वही विषाक्त चिंतन पं.नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दौर से गुजरते हुए आज राहुल गांधी के समय तक पार्टी की नस–नस में समा गया है। अब कांग्रेस नेतृत्व का एकमात्र मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना रह गया हैकृ चाहे इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा–अखंडता को दांव पर लगाकर भारत की प्रतिष्ठा को ही धूमिल क्यों न करनी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को मुस्लिम–लीगी माओवादी कांग्रेस कहने और उसे देश के लिए खतरा बताने का निहितार्थ क्या है? इस विचार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार नहीं, बल्कि तीन अवसरों पर व्यक्त किया हैं। पहले 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग गठबंधन द्वारा दर्ज प्रचंड जीत पर दिल्ली में भाजपा समर्थकों को संबोधित करते हुए। फिर 15 नवंबर को गुजरात स्थित सूरत के एक कार्यक्रम में और इसके बाद 17 नवंबर को दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका व्याख्यान में। प्रधानमंत्री के मुताबिक, 10–15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन–नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, अब वो कांग्रेस को श्मुस्लिम–लीगी माओवादी कांग्रेस्य (एम.सी.सी.) बना चुके हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुस्लिम–लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ मेंज् देश के लिए खतरा बनते जा रही है। कांग्रेस की यह छवि एकाएक नहीं बनी है और न ही यह मात्र कोई चुनावी या राजनीतिक जुमलेबाजी है। कांग्रेस का संकट बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर उसके आधिकारिक वक्तव्य से स्पष्ट है, जिसमें पार्टी नेतृत्व मतदाता द्वारा नकारे जाने को फर्जी वोट चोरी का परिणाम बता रही है। दरअसल, वर्तमान कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता–विपक्ष राहुल गांधी जिस विभाजनकारी मार्ग पर चल रहे है, उसकी प्रेरणा उन्हें अपने परिवार ही से मिली है। वर्ष 1950 से राहुल के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस विकृत सेकुलरवाद को अपनाया, उसने देश में इस्लामी कट्टरता और हिंदू–विरोधी शक्तियों को नया जीवनदान दिया। पहले उन्होंने जम्मू–कश्मीर के इस्लामी स्वरूप को बरकरार रखने हेतु अनुच्छेद 370–35ए को संविधान में बिना चर्चा के श्चोर दरवाजेय से शामिल करवाया, तो बहुसंख्यकों के लिए शहिंदू कोड बिलय लागू करके मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम समाज को हलाला और तीन तलाक जैसी कुरीतियों के साथ छोड़ दिया। पं।नेहरू के लिए हिंदू मंदिर दमनकारी, तो केवल हिंदू ही सांप्रदायिक थे। कालांतर में उनके द्वारा अपनाई समाजवाद प्रेरित नीतियों ने भारतीय आर्थिकी को ध्वस्त कर दिया, जिसकी चर्चा पिछले कुछ लेखों में की जा चुकी है। यह विकृति राहुल की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में और बढ़ गई। उन्होंने 1969 में कांग्रेस टूटने के बाद अपने धड़े की वैचारिक संगोष्ठी उन वामपंथियों के हाथों में सौंप दी, जो अधिनायकवाद को बढ़ावा देने के साथ न तो तब स्वयं को भारत की बहुलतावादी सनातन संस्कृति से जोड़ पाए थे, न ही अब जोड़ पाते है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत द्वारा अपनी वोट चोरी पकड़े जाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल (1975–77) थोप दिया। इसी दौरान अयोध्या में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के प्रमाण संबंधित उत्खनन रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। कालांतर में पंजाब में अपनी विरोधी अकाली दल को हाशिए पर पहुंचाने हेतु उन्होंने मृत श्खालिस्तान्य विचार को अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता हथियाने की लालसा में पुनर्जीवित कर दिया। इसका उल्लेख गैर–राजनीतिक, पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय खुफिया एजेंसी शरिसर्च एंड एनालिसिस विंगय (रॉ) में वर्षों जुड़े रहने के बाद सेवानिवृत हुए गुरबख्श सिंह सिधू ने अपनी पुस्तक श्द खालिस्तान कांस्पीरेसीय में किया है। जैसे 1980 के दशक में जरनैल भिंडरावाले को आगे रखकर इंदिरा गांधी ने हिंदू–सिख संबंधों को लेकर आत्मघाती राजनीति की, ठीक उसी तरह राहुल के पिता राजीव गांधी ने वर्ष 1986 के शाहबानो मामले से श्मुस्लिम वोटबैंक्य का बिगुल फूंक दिया। तब मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए तत्कालीन राजीव सरकार ने संसद में प्रचंड बहुमत के बल पर मुस्लिम महिला उत्थान की दिशा में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था। कालांतर में मुस्लिम–विरोध के कारण ही सलमान रुश्दी की श्सैटनिक वर्सेजय (1988) और तस्लीमा नसरीन की श्लज्जाय (1993) पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (दिवंगत) डॉ. मनमोहन सिंह 2004–2014 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे, परंतु उन्हें दिशानिर्देश असंवैधानिक श्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्य (एन.ए.सी.) से मिलते थे, जिसका नेतृत्व तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा और राहुल की माताजी सोनिया गांधी कर रही थीं। एन।ए।सी। में ऐसे लोग शामिल थे, जिनका राष्ट्रहित के बजाय वैचारिक एजेंडे (वामपंथ सहित) से अधिक सरोकार था। इसी कालखंड में 2002 के उस नृशंस गोधरा कांड, जिसमें जिहादियों ने भजन–कीर्तन कर रहे 59 हिंदुओं को ट्रेन में जिंदा जला दिया थाकृ उसे हादसा बताकर रफादफा करने का असफल प्रयास किया गया। घुमा–फिराकर देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बता दिया। हलफनामा देकर सर्वोच्च न्यायालय में मर्यादापुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को काल्पनिक कह दिया। वैश्विक रूप से स्थापित जिहादी आतंकवाद–कट्टरवाद को तब देश में श्इस्लामोफोबियाय घोषित करने हेतु मनगढ़ंत शहिंदू–भगवा आतंकवादय का हौव्वा खड़ा कर दिया। इसके अंतर्गत, वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले (26द्11) में असली दोषी (पाकिस्तानी आतंकियों) को क्लीनचिट देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फंसाने का फर्जी नैरेटिव बुना गया। यासीन मलिक जैसे खूंखार जिहादियों से सहानुभूति रखते हुए उसे राजकीय मंच दिया गया। यहां तक, एन.ए.सी. के मार्गदर्शन में तब कांग्रेस सरकार ने वह विषाक्त सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक भी संसद से पारित कराना चाहा, जिसके तहत केवल बहुसंख्यककृ अर्थात् हिंदू को ही किसी सांप्रदायिक हिंसा के लिए दोषी मानने का प्रावधान था। वर्ष 2014 से कांग्रेस अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार तीन लोकसभा चुनाव और दर्जनों विधानसभा चुनाव हार चुकी है।

युवती की हत्या, पॉश इलाके में मिला शव

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर के विशालखंड दो में एक युवती की हत्या कर दी गई। उसका शव सड़क किनारे दीवार के सहारे टिकाकर बदमाश भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ संदिग्ध दिखे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। अज्ञात पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। प्रारंभिक छानबीन में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। एसीपी गोमतीनगर बृज नारायण सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसीपी के मुताबिक शव की पहचान अलीगंज सेक्टर–बी के फत्तेपुर निवासी चंद्रप्रकाश की बेटी रेखा वर्मा (35) के रूप में हुई है। चंद्रप्रकाश पीडब्ल्यूडी में रोलर चालक थे, जिनका देहांत हो चुका है। रेखा के भाई राकेश ने बताया कि रविवार पूर्वाह्न 11 बजे उनकी बहन घर से निकली थी। देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन की। काफी देर तक तलाश के बाद भी रेखा का पता नहीं चल सका।

सोमवार सुबह शव मिलने के बाद पुलिस ने शिनाख्त का प्रयास किया। युवती के हाथ पर टैटू बना था, जिसकी मदद से परिजनों से संपर्क किया। देर शाम को परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। छानबीन में सामने आया है कि युवती का शव घसीटकर वहां लाया गया था। मौके पर इसके साक्ष्य भी मिले हैं। कपड़े भी अस्त–व्यस्त थे। यही नहीं, शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेखा ने हत्यारों से संघर्ष किया था। दोनों हाथ अकड़ गए थे। परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हत्यारों ने साजिश के तहत शव को नाले के पास बनी दीवार के सहारे टिका दिया था। वहां से गुजरने वाले लोगों को लगा कि युवती दीवार के सहारे बैठी हुई है। युवती को काफी देर तक बैठा देख लोगों को संदेह हुआ। पास जाकर आवाज लगाने पर युवती ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए। सूत्रों का कहना है कि रेखा ने कुछ दिन पहले जमीन बेची थी। आरोप है कि रुपयों की लालच में परिचित युवक उनके पीछे पड़ा था। उसी के बुलाने पर रेखा घर से निकली थीं। आशंका है कि परिचित युवक ने ही साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी।

आउटसोर्सिंग के जरिये रखे जाएंगे फोरेंसिक एक्सपर्ट

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में फील्ड यूनिट्स के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के 758 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिये भर्ती की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने इसकी सूचना दी है। यह कदम प्रदेश में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रयोगशाला परीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। चयन में एफएसीटी और एफएसीटी

प्लस (फॉरेंसिक एप्टीट्यूट एंड कैलिबर टेस्ट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। डीजीपी मुख्यालय के मुताबिक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रेड–1 के 75, ग्रेड–2 के 183 और ग्रेड–3 के 500 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए शैक्षिक योग्यता बीएससी और एमएससी है। चयन के बाद फोरेसिंक एक्सपर्ट से घटनास्थल संरक्षण, वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन, पैकिंग, लेबलिंग, फॉरवर्डिंग का कार्य करना होगा। इससे विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की तकनीकी परीक्षण प्रक्रिया मजबूत होगी। जल्द ही भर्तियों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर जारी होगी।

संक्षिप्त खबरें

अमेठी में छात्राओं ने रोड पर लगाया जाम

लखनऊ, (संवाददाता)। अमेठी में बाजारशुक्ल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने मंगलवार को विद्यालय में कार्यरत दो शिक्षिकाओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाते थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपा है। छात्रा आंशी शुक्ला, रोशनी साहू, शिवानी चौरसिया, नंदनी सरोज, दिव्यांशी और आर्या ने आरोप लगाया कि विद्यालय में तैनात शिक्षिका आर्यना वोध और रंजना देवी उन्हें व अन्य बच्चियों को लगातार प्रताड़ित करती हैं। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने इन्हौंना–रुदौली मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि दोनों शिक्षिकाएं सहपाठी छात्राओं को उकसाकर उनसे गाली–गलौज और मारपीट करवाती हैं, जिससे वे शांति से पढ़ लिख नहीं पा रहीं। प्रार्थनापत्र में छात्राओं ने यह भी कहा कि शिक्षिकाओं का विद्यालय की प्रिंसिपल से मनमुटाव चल रहा है और इसकी खुन्नस हे बच्चों पर निकाल रही हैं। छात्राओं के अनुसार, हाल ही में हुई जांच में उन्होंने सही जानकारी दी थी, जिसके कारण शिक्षिकाएं उनसे बदले की भावना रखती हैं। थानाध्यक्ष विवेक शर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

अचानक सामने सांड आने से नहीं संभली बोलेरो

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के सीतापुर में मंगलवार सुबह एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जबकि, छह अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। वहां से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसा सिधौली कोतवाली क्षेत्र के महमूदाबाद मार्ग पर टड़ई पुल के पास हुआ। मूल रूप से खरवलिया का मजरा बिहार पुरवा निवासी शिवबचन (68) अपने छह रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह में सिधौली गए थे। सुबह वहां से लौटकर घर जा रहे थे। टड़ई पुल के पास वाहन अनियंत्रित हो गया। जब तक चालक संभालता गाड़ी सड़क किनारे खड्ड में जा गिरी। हादसे में शिवबचन सहित सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को सीएचसी, सिधौली पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने शिवबचन को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुरोध पर सभी को लोहिया अस्पताल, लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार, अचानक आवारा सांड सामने आ गया। उसे बचाने में गाड़ी अनियंत्रित हो गई।

सच्ची भक्ति के लिए मन का साफ होना जरूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। बालागंज के सिटी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में सोमवार को गायत्री यज्ञ और भजन संध्या का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के कार्यक्रम में साध्वी निष्ठा ने कहा कि साफ मन वाले लोग ईश्वर को को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। सच्ची भक्ति के लिए मन का साफ होना जरूरी है। जो लोग ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। ऐसे लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं।

चार वार्डों में सफाई व्यवस्था बदहाल, जोनल अधिकारी को पड़ी फटकार

लखनऊ, (संवाददाता)। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार सुबह जोन आठ इलाके में आने वाले पांच वार्डों में सफाई

व्यवस्था की हकीकत परखने के लिए निरीक्षण किया। चार वार्डों में सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। उन्होंने जोनल अधिकारी विकास सिंह, जोनल सेनेटरी अधिकारी जितेंद्र गांधी और क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक मीरा राव को फटकार लगाई और एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। इस दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौजूद रहीं। मंत्री सबसे पहले खरिका प्रथम वार्ड पहुंचे, जहां तेलीबाग, सुभानी खेड़ा, देवी खेड़ा और मोहारीबाग क्षेत्रों में नालियां चोक मिलीं। सड़कों पर गंदगी थी। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। जोनल अधिकारी मौके पर नहीं मिले तो वह नाराज हुए। पता चला कि वह दूसरे जगह पर हैं। जब वह पहुंचे तो उनको मंत्री ने कड़ी फटकार लगाई, पूछा कभी फील्ड में निकलते हो या ऑफिस में बैठे रहते हो। इसके बाद मंत्री खरिका द्वितीय वार्ड में पहुंचे। यहां पर कांशीराम कॉलोनी में जल निकासी व्यवस्था चोक मिली। जिसको लेकर सफाई कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, नम्रता सिंह व मुख्य अभियंता सिविल महेश वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के ईश्वरी खेड़ा गांव में सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विस्तारित क्षेत्र की उपेक्षा न की जाए। गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए।

बकायेदार आए, सवाल पूछे और दोबारा आने का वादा करके लौट गए

लखनऊ, (संवाददाता)। बिजली बिल राहत योजना 2025 की शुरुआत के पहले दिन शहर के विभिन्न कार्यालयों और बिलिंग केंद्रों पर बकायेदारों की अच्छी–खासी भीड़ जुटी। बकायेदारों ने कर्मियों से पूछा... कितनी रकम जमा करनी होगी, किश्तें कब तक देनी होंगी, और बिल भरते रहने के बावजूद देनदारी क्यों दिख रही है? कर्मियों ने पंजीकरण कराने की अपील की तो कई बकायेदार मुस्कराते हुए बोले कि अगली बार आएंगे और फिर लौट गए। पहले दिन 1.13 लाख बकायेदारों में से केवल 200 ने पंजीकरण कराया। इनमें सर्वाधिक संख्या अमौसी जोन की रही। बकायेदारों की सुविधा के लिए उपकेंद्रों समेत विभिन्न कार्यालयों पर पंजीयन शिविर भी लगाए गए। साथ ही देनदारों को नोटिस रिसीव कराए जाने का सिलसिला शहर से गांव तक जारी रहा। योजना की प्रगति पर नजर रखते हुए मुख्य अभियंता वीपी सिंह, सुशील गर्ग,

रवि अग्रवाल और महफूज आलम ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में अधिक लोग बिल जमा करने आगे आएंगे। बड़े बिल वाले निकले फकीरे, मिली 1.25 लाख की छूट मलिहाबाद खंड अंतर्गत काकोरी के नौबस्ता निवासी फकीरे ने योजना का लाभ लेते हुए 1.25 लाख रुपये की छूट पाई। मुख्य अभियंता महफूज आलम के मुताबिक फकीरे पर 1,76,771 रुपये का बकाया था जिसमें 1,08,226 रुपये ब्याज शामिल था। पंजीकरण के रूप में 2,000 रुपये जमा कर उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट (17,136 रुपये) भी हासिल की और केवल 51,409 रुपये जमा करके बकाया कर्ज से मुक्त हो गए।

संक्षिप्त खबरें

मयूर चमके, प्रेस एकादश की आसान जीत

लखनऊ, (संवाददाता)। मयूर शुक्ला के बहुमुखी प्रदर्शन (69 रन और दो विकेट) की बदौलत प्रेस एकादश ने महापौर एकादश को आसान मुकाबले में आठ विकेट से मात देते हुए नगर निगम क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया। महापौर एकादश के 120 रन के लक्ष्य

को प्रेस एकादश ने 18.4 ओवर में दो विकेट खोकर प्राप्त किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेली जा रही प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में महापौर एकादश ने 25 ओवर में आठ विकेट खोकर 119 रन बनाए। शिवपाल सावरियां ने सबसे अधिक 32 और लवकुश ने 16 रन का योगदान दिया। वैभव तिवारी ने तीन और इश्तियाक रजा व मयूर शुक्ला ने दो–दो विकेट झटके। जवाब में प्रेस एकादश ने मयूर के 69 रन की बदौलत 18.4 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। टीम से विवेक चौहान ने 13 और सुधीर तिवारी ने 12 रन बनाए। अनुराग मिश्रा को एक विकेट मिला। इससे पहले महापौर सुषमा खर्कवाल ने खिलाड़ियों से परिचय लेने के बाद बल्लेबाजी करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

रोडवेज संविदा चालक के 120 पद, पहुंचे सिर्फ 25 अभ्यर्थी

लखनऊ, (संवाददाता)। रोडवेज में संविदा पर बस चालक की नौकरी को लेकर रुझान कम है। यही वजह है कि अवध बस अड्डे पर सोमवार को शुरू हुए दो दिवसीय रोजगार मेले के पहले दिन महज 25 अभ्यर्थी ही पहुंचे। इनमें दो अनुपयुक्त पाए गए। एक अभ्यर्थी प्रथम चालक टेस्ट के दौरान नहीं आया। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि संविदा बस चालकों के 120 पदों के लिए लखनऊ परिक्षेत्र की ओर से दो दिवसीय रोजगार मेला लगाया गया। सत्यापन में दो के दस्तावेजों के अनुपयुक्त पाए गए। शेष 23 के दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रथम चालक टेस्ट के लिए बुलाया गया। इस दौरान एक अभ्यर्थी नहीं आया। सभी 22 अभ्यर्थी प्रथम चालक टेस्ट में सफल रहे। अब उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दूसरे चालक टेस्ट के लिए कानपुर स्थित प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान एलेन फॉरेस्ट भेजा जाएगा। पास होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी के अभाव में ही पहले दिन कम लोग आए हैं।

2047 के विकसित भारत विजन में उत्तर प्रदेश निभाएगा नेतृत्वकारी भूमिका

लखनऊ, (संवाददाता)। होटल क्लार्क अवध में आज आयोजित विकसित यूपी कॉन्क्लेव में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में नीति आयोग, नियोजन विभाग, फिक्की और चौंबर ऑफ कॉमर्स के विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया ।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। आज प्रदेश में 25,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 3,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 200 से अधिक विशिष्ट अस्पताल और 81 मेडिकल कॉलेज सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 102द108 एंबुलेंस सेवा को और अधिक सक्षम बनाया गया है तथा इसका रेस्पॉन्स टाइम कम हुआ है, जिससे आपातकालीन सेवाओं की गति और प्रभावशीलता में बड़ी वृद्धि हुई है ।ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार का लगातार प्रयास है कि संस्थागत प्रसव दर बढ़े और मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी आए। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब पहले से अधिक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनता को बड़ा लाभ मिला है ।उन्होंने कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को वही आधुनिक और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो आज केवल महानगरों तक सीमित हैं। सरकार का लक्ष्य है कि एडवांस मेडिकल सेवाएं जिला और तहसील स्तर तक पहुंचें ।

विश्व एड्स दिवस पर लखनऊ में भव्य जन–जागरूकता रैली, 2500 से अधिक विद्यार्थियों की उत्साही भागीदारी

लखनऊ, (संवाददाता)। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आज लखनऊ में जागरूकता का एक भव्य और प्रभावशाली आयोजन किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर से हजरतगंज चौराहे तक निकाली गई विशाल जागरूकता रैली में करीब 2500 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जो शहर के विभिन्न महाविद्यालयों की एनएसएस और एनसीसी इकाइयों से जुड़े हुए थे। हाथों में एचआईवी जागरूकता संबंधी तख्तियां और झंडे लिए छात्र–छात्राओं की टुकड़ियों ने पूरे मार्ग में लोगों का ध्यान आकर्षित किया और एड्स उन्मूलन का मजबूत संदेश दिया ।रैली विश्वविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम, परिवर्तन चौक होते हुए हजरतगंज पहुँची और वहां से पुनः विश्वविद्यालय परिसर लौटकर सम्पन्न हुई। इस जागरूकता रैली को उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अपर परियोजना निदेशक रविंद्र कुमार और लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्ग में हजारों की संख्या में नागरिकों ने छात्रों के इस प्रयास की सराहना की ।अपर परियोजना निदेशक रविंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि एचआईवी– एड्स से जुड़ी जागरूकता किसी भी संवेदनशील और जागरूक युवा की पहचान है। उन्होंने कहा कि समाज में मौजूद भ्रांतियों को दूर करना समय की आवश्यकता है, और इस दिशा में युवा पीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एड्स प्रभावित व्यक्तियों को भी समाज का समान सदस्य समझें और उनके अधिकारों का सम्मान करें। उन्होंने सभी युवाओं को एड्स उन्मूलन के लिए चल रही राज्य सोसाइटी की मुहिम में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया ।रैली के उपरांत सीतापुर से आए जादूगर मुन्ना एंड पार्टी ने मनोरंजक जादू कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें जागरूकता संदेशों को रचनात्मक ढंग से शामिल किया गया। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम में उत्साह भर दिया ।इस अवसर पर मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। अपने संबोधन में मंडलायुक्त पंत ने कहा कि अब समय बदल चुका है और एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को अछूत मानने जैसी सोच समाप्त हो रही है। एंटी–रेट्रो वायरल थेरेपी के माध्यम से आज एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि एड्स उन्मूलन का लक्ष्य केवल एड्स नियंत्रण सोसाइटी का नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है ।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आमंत्रित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिनमें रमेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉ. गीता अग्रवाल, दिनेश सिंह, डॉ. संजय सोलंकी, अनुज दीक्षित, डॉ. अमरेंद्र सिंह, पवन चंदेल और नरेंद्र सिंह शामिल थे। सभी ने जागरूकता अभियान की सराहना की और इसे समाज हित में अत्यंत आवश्यक बताया।

नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और निवेश माहौल को सुदृढ़ करने पर दिया जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। होटल ताज में आयोजित इंडियन इनवेस्टर्स फेडरेशन के 10वें बैंकिंग लीडरशिप समिट एवं अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर मंत्री नन्दी ने बैंकिंग सेवा और उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के अधिकारियों और प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में हजारों करोड़ का निवेश करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया ।इस समिट में देश के प्रमुख बैंकर, नीति–निर्माता, उद्योगपति, वित्तीय विशेषज्ञ, वरिष्ठ नौकरशाह, शिक्षाविद् और उद्यमी एक मंच पर एकत्र हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को अगले दौर की आर्थिक छलांग दिलाना, निवेश प्रवाह बढ़ाना, एमएसएमई सशक्तिकरण, क्रेडिट सुधार और नई औद्योगिक रणनीतियों पर विचार–विमर्श करना था ।मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक उच्च–विश्वास और उच्च–दक्षता वाला औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जो वैश्विक मानकों पर पूरी तरह खरा उतरेगा। उन्होंने निर्यात–उन्मुख उद्योगों के तेज विकास, एनआरआई निवेश को सुगम बनाने, विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग जोन और लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण तथा मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और हाई–टेक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। उन्होंने राज्य की औद्योगिक विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला ।उद्घाटन सत्र को टीजीआई एसएमई कैपिटल, मुंबई के सीईओ अजय ठाकुर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। राज्य का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत तक पहुंचा है, बारह कंपनियों का एसएमई लिस्टिंग हुआ है, पूंजी प्रवाह बढ़ा है और उद्यमियों में वित्तीय जागरूकता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। कैनरा बैंक के अजित कुमार मिश्रा ने बताया कि उनका बैंक उत्तर प्रदेश को वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में पूर्ण सहयोगी है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस–वे, इथेनॉल उत्पादन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्त पोषण किया जा रहा है ।रेडिको खेतान के साकेत ने प्रति व्यक्ति आय में जीडीपी से भी तेज वृद्धि को राज्य की बढ़ती क्रय शक्ति का प्रमाण बताया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अजय खन्ना और बैंक ऑफ इंडिया के अमरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना और अन्य एमएसएमई योजनाओं में सहज और त्वरित वित्त पोषण की जानकारी साझा की। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक ब्रजेश कुमार सिंह ने डिजिटल लेंडिंग, औद्योगिक क्रेडिट के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की औद्योगीकरण में निर्णायक भूमिका पर जोर दिया ।समिट का समापन भव्य अवार्ड सेरेमनी के साथ हुआ जिसमें बैंकिंग, उद्योग, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। अदाणी ग्रुप, रेडिको ग्रुप, अमूल, मानसिंह गोयल ग्रुप, नवभारत डिफेंस सिस्टम सहित अनेक प्रमुख संस्थानों को उद्योग एवं कॉर्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। बैंकिंग श्रेणी में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आदि ।

2.31 करोड़ से बदलेगी बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की सूरत

लखनऊ, (संवाददाता)। आलमनगर स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की सूरत बदलेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 2.31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त रूप में नजर आएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मंदिर के कई हिस्सों में सुधार कार्य तेजी से चल रहा है, जिनमें नया ग्रेनाइट मार्ग, संरचनात्मक सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वॉल और नया मुख्य प्रवेश द्वार शामिल है। नया ग्रेनाइट मार्ग लगभग तैयार है। साथ ही मंदिर की सीमा को सुरक्षित रखने और कटाव रोकने के लिए मजबूत रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। नया बड़ा प्रवेश द्वार भी तैयार हो रहा है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में पौधों की प्रतिरक्षा पर शोध जरूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर चल रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन सोमवार को जलवायु परिवर्तन से निपटने में पादप विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की। एनबीआरआई के निदेशक डॉ. अजित के. शासनी ने पौधों की आंतरिक प्रतिरक्षा को जलवायु परिवर्तन से उपजे तनावों के समाधान में उपयोगी ठहराते हुए इनके गहन शोध की जरूरत बताई । प्लेनरी सत्र में डॉ. जेसन सी. व्हाइट ने अमेरिका से ऑनलाइन जुड़कर नैनो बायोटेक्नोलॉजी आधारित फसल तनाव–सहनशीलता पर व्याख्यान दिया। तकनीकी सत्रों में जैव–विविधता, पुराविज्ञान, पर्यावरणीय सूक्ष्मजीव विज्ञान, प्रकृति–आधारित तकनीकों और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण जैसे उभरते खतरों पर विशेषज्ञों ने बहु–विषयक दृष्टिकोण पेश किया।

मेडिकल कालेज जौनपुर में वार्षिक उत्सव का तीसरा दिन उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया

देश की उपासना ब्यूरो

जौनपुर । उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के प्रधानाचार्य प्रो० आर०बी० कमल के कुशल नेतृत्व में नोडल वार्षिक उत्सव डा० मुदित चौहान एवं डा० पूजा पाठक के द्वारा आज वार्षिक उत्सव के तीसरे दिन अत्यंत उत्साह, सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के तीसरे दिन खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की एक उत्साहपूर्ण श्रृखला देखने को मिली। छात्रों ने अत्यधिक ऊर्जा और जोश के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिनभर चले आयोजनों में प्रमुख रूप से एथलेटिक्स प्रतियोगिताएँ, बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्रिकेट मैच एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम–नृत्य संगीत एवं रंगारंग प्रस्तुतियाँ बड़े ही आनन्दमय वातावरण में सम्पन्न हुआ। मेडिकल कालेज जौनपुर के वार्षिक उत्सव का यह तीसरा दिन न केवल प्रतिभा प्रदर्शन का मंच बना, बल्कि छात्रों में आपसी समन्वय, खेल भावना और सांस्कृतिक चेतना को भी मजबूत करने वाला साबित हुआ। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि समय निकालकर चिकित्सकों ने भी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी सहभागिता ने उत्सव की गरिमा, उत्साह और प्रेरणदायक माहौल को और अधिक ऊँचा किया। प्रधानाचार्य प्रो० आर०बी० कमल ने अपने संबांधन में कहा कि मेडकल कालेज जौनपुर के छात्र–छात्राएँ इस वार्षिक उत्सव में भाग लेकर न केवल आनंद प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि इसे अपने स्वास्थ्य को चुस्त–दुरूस्त रखने, खेल भावना विकसित करने और सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी देख रहें है। विभिन्न प्रतियोगिताएँ विधार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ‟कॉलेज प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष और अधिक सुदृढ़ रूप में किया जए, ताकि किसी भी प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर न छूटे। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य हैं। प्रधानाचार्य महोदय ने कार्यक्रम के कुशल संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजन समिति, सभी शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्र–छात्राओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‟आप सभी के सहयोग, अनुशासन और शांतिपूर्ण सहभागिता से यह आयोजन प्रतिदिन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।‟ और आशा करता हूँ कि आगे कार्यक्रम के शेष दिनों में इससे बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मेडिकल कालेज प्रशासन ने इस कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भविष्य में और भी उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो० ए०ए० जाफरी, डीन रिसर्च प्रो० रूचिरा सेठी, डीन एकेडमिक प्रो० तबस्सुम याशमीन, स्पोर्ट कमेटी अध्यक्ष, प्रो० उमेश कुमार सरोज, प्रो० भारती यादव, डा० साधना अजय, डा० विनोद डा० अरविन्द पटेल, डा० आदर्श कुमार यादव, डा० सी०बी०एस० कर्नल पटेल, डा० अनुज सिंह, डा० सरिता पाण्डेय, डा० राजश्री यादव, डा० स्वाती विश्वकर्मा, डा० अचल सिंह, डा० रोहित कुमार सरोज, डा० चन्द्रभान, डा० आशुतोष सिंह, डा० विनोद वर्मा, डा० अर्चना, डा० अनिल, डा० प्रियंका सिंह, डा० रेनू, डा० बृजेश कन्नौजिया, डा० अजय, डा० पंकज, डा० जयंत शर्मा, डा० संदीप सिंह, डा० दिग्वेश, डा० मतीन अहमद एवं एम०बी०बी०एस० व पैरामेडिकल छात्र/छात्राएं तथा कर्मचारी उपस्थित रहें।

कर्नाटक और हरियाणा ने दर्ज की जीत, खेल मंत्री ने किया प्रतियोगित का उद्घाटन

गोरखपुर, (संवाददाता)। ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का सोमवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबला कर्नाटक बनाम गुजरात के मध्य खेला गया। इसमें कर्नाटक ने गुजरात को रोमांचक मुकाबले में 39–24 अंकों के अंतर से पराजित करते हुए आगे की राह बनाई। कर्नाटक की तरफ से कृपा सागर ने रेड में 10 अंक और चेतन नायक ने डिफेंस में आठ अंक बनाए। गुजरात टीम की तरफ से किशन पांडेय ने रेड में आठ अंक और आशीष सरसरे ने डिफेंस में नौ अंक दिलाए। दूसरा मैच हरियाणा बनाम छत्तीसगढ़ के मध्य खेला गया।

जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व मामलों के निस्तारण में जौनपुर प्रथम स्थान पर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के नेतृत्व में राजस्व विभाग द्वारा राजस्व सम्बन्धी वादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है जिसके फलस्वरुप राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) द्वारा नवंबर माह की जारी रिपोर्ट में जनपद स्तरीय न्यायालय में राजस्व के मामले के निस्तारण में एक बार फिर जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनपद स्तरीय न्यायालयों में राजस्व वादों के निस्तारण में पिछले 14 माह से जनपद टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार राजस्व मामलों को निस्तारित किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू की नवंबर माह की राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की रिपोर्ट के अनुसार जनपद की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक के निस्तारण से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जनपद जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के सापेक्ष 367 मामलों का निस्तारण किया है। इसका अनुपात 146.80 प्रतिशत है। इसी के साथ जनपदीय न्यायायल में राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह नवंबर में जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी न्यायालय ने निर्धारित 30 मामलों के मानक के मुकाबले 68 मामलों का निस्तारण कर 226.67 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की, जो की प्रदेश भर में सबसे अधिक है और जौनपुर प्रदेश भर में पहले स्थान पर है।

एसआईटी द्वारा कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में लगातार कार्रवाई जारी तीन दिनों में कुल 30 बैंक खाते फ्रीज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में एसआईटी द्वारा कोडिन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले तीन दिनों में कुल 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। इनमें गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल समेत जनपद के सात फर्म संचालकों के खाते शामिल हैं। अब तक 16 अन्य खाते भी चिह्नित किए गए हैं, और फर्म संचालकों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष नजर है। एसआईटी अब ट्रांसपोर्टरों और फर्म संचालकों के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। जौनपुर एसआईटी के अनुसार, गोपाल कटरा ढालघर टोला स्थित हर्ष मेडिकल स्टोर के संचालक संजीव चौरसिया के पांच बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। इस स्टोर से वर्ष 2023 से अब तक 17 हजार शीशी (प्रत्येक 100 एमएल) कोडिन युक्त न्यू फेन्साडिल कफ सिरप की बिक्री दिखाई गई है।इस मामलेंमें बुधवार को जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी शहर गोल्डी गुप्ता ने बताया कि इसी क्रम में, नईगंज कटघरा स्थित बद्रीनाथ फार्मेसी एंड सर्जिकल के मालिक विवेक यादव के भी दो बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। जांच टीम के अनुसार, इन स्थानों से भी कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। एसआईटी ने गिरोह के सरगना वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल, जो सोनभद्र एसआईटी के हत्थे चढ़े हैं, उनसे पूछताछ के लिए जौनपुर एसआईटी की टीम सोनभद्र जाएगी और उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस मामले में दो मुकदमों में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इनकी तलाश में कई जगह दबिश दी, लेकिन कोई आरोपी नहीं मिला। अब पुलिस कोर्ट से गैर–जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कराकर इनकी गिरफ्तारी करेगी। यह सिरप तस्करी का खेल वर्ष 2023 से चल रहा था। जांच में सामने आया है कि कोडिन युक्त न्यू फेन्साडिल कफ सिरप की 1.27 लाख शीशियां (प्रत्येक 100 एमएल) शैली ट्रेडर्स, रांची से खरीदी गई थीं। इन्हें वाराणसी के काशी फार्मा, गैलेक्सी मेडिकल एजेंसी, गाजीपुर के महादेव मेडिकल एजेंसी, प्रतापगढ़ के महादेव एजेंसी और आजमगढ़ के एएस फार्मा को बेचने की बात कही गई है।

संक्षिप्त खबरें

अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी हुई सील

अयोध्या। जिले में अवैध रूप से तथा बिना मानक के संचालित पैथोलॉजी पर सीएमओ सुशील कुमार के निर्देश पर गठित टीम में शामिल अधिकारी शिकंजा कसने में जुटे हुए हैं। वहीं अब तक पिछले दिनों आधा दर्जन से अधिक अनधिकृत रूप व अवैध रूप से चलते हुए

पाए जाने पर अगले आदेश तक सील किया गया। मंगलवार को भी सीएमओ द्वारा गठित टीम मे शामिल डॉ आशुतोष श्रीवास्तव नोडल नैदानिक स्थापना,डॉ राजेश चौधरी नोडल झोलाछाप व ए0आर0ओ0 सद्दाम तीन सदस्यीय टीम ने देवकाली,दर्शन नगर मे पैथ लैब का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान राज पैथ लैब निकट बिग बाजार के समीप जो अनधिकृत रूप से चल रही थी। जिसे इस टीम में शामिल सदस्यों ने उक्त पैथोलॉजी को सील किया।

जनपद में लगभग 100 बीएलओं ने शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है : जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ और सुपरवाइजर से गणना प्रपत्र वितरण और संग्रहण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और कम प्रगति वाले बीएलओ को निर्देशित किया कि अवशेष गणना प्रपत्रो का शत–प्रतिशत वितरण और संग्रहण कर डिजीटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें, जिससे ससमय विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईआरओ, एईआरओ को निर्देशित किया कि अतिरिक्त कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर गणना प्रपत्र वितरण, संग्रहण और डिजीटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें। जिन बूथो पर अपेक्षाकृत कम प्रगति है, वहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि बीएलओ का सहयोग करते हुए इस कार्य को पूर्ण कराये। उन्होने इस कार्य में लगे सभी कार्मिकों से प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी लोग पूरे मनोयोग से कार्य करें। उन्होने बताया कि जनपद में लगभग 100 बीएलओं ने शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिन्हे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है और भविष्य में भी इसी प्रकार सम्मानित कर उनके कार्यो की सराहना की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भू–राजस्व अजय अम्बष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेन्द्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह, तहसीलदार सदर, सुपरवाइजर, बीएलओ सहित अन्य उपस्थित रहे।

अर्न्तराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रचना विशेष विद्यालय में विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर 03 दिसम्बर, अपर सिविल जज सी0डि0 प्रथमधप्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में ‟अर्न्तराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस'' के विषय पर 03 दिसम्बर 2025 को ‟रचना विशेष विद्यालय बल्लोच टोला सिपाह, जौनपुर'' में विधिक साक्षरताध जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जि0वि0से0प्रा0, जौनपुर डॉ0 दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है विश्व का हर व्यक्ति अंदर या बाहर से कहीं न कहीं विकलांग होता है और महान प्रतिभाएं और महान वैज्ञानिक दार्शनिक आइंस्टीन स्टीफन हॉकिंस अष्टावक्र जैसे अधिकांश विश्व विख्यात विभूतियां विकलांग होते हुए भी सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता केंद्र डिफेंस सिस्टम पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सिस्टम, फ्रंट ऑफिस सिस्टम, लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत एवं अन्य बातों के बारे में बताते हुए कहा कि दिव्यांग जन के लिए सरकारी और विधिक सहायता उपलब्ध हैं और इसको कार्य रूप में पारित करने के लिए न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका मिलकर प्रयास कर रहे हैं उन्होंने लोगों को आगे जाकर दिव्यांग लोगों की भरपूर मदद करने का आवाहन किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग एक परिवर्तनकारी अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के कानून 1995, 2016 और संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तृत विवरण देते हुए कहा की इसमें विकलांग व्यक्तियों की हर प्रकार से सुरक्षा और संरक्षा की गई है। जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने कहा की सरकार हर स्तर से दिव्यांगों की मदद के लिए कृत संकल्प है और वह अपने स्तर से अपने विभाग के साथ दिव्यांग लोगों की मदद के लिए कृत संकल्प हैं उन्होंने विभाग की ओर सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों को कभी हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए और ना उन्हें निराशा या हताश होना चाहिए इन बच्चों की मदद करने वाले लोग बहुत महान होते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना राष्ट्रीय स्तर की तमाम योजना और मंदबुद्धि लोगों के लिए सरकार की योजना के साथ ब्रेल लिपि के बारे में भी बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस एवं काउंसलर पारिवारिक न्यायालय के देवेंद्र कुमार यादव ने कहा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर दिव्यांग बच्चों की हर प्रकार से मदद और सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने महत्वपूर्ण विधिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे महान गुण और जन्मजात प्रतिभाओं से युक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि विकलांग दिव्यांग व्यक्ति लोगों के लिए बस स्टैंड हवाई जहाज में ट्रेन में और शौचालय से लेकर प्लेटफार्म तक विशेष व्यवस्था की जाती है यहां तक कि उनके मतदान की भी अलग व्यवस्था होती है। सभी अतिथि गण का स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। परी नमक 5 साल की नन्ही बच्ची द्वारा बहुत ही सुंदर और भाव विभोर कर देने वाला गीत भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी दिव्या शुक्ला, डिफेंस काउंसिल डॉ0 दिलीप कुमार सिंह, काउंसलर देवेंद्र कुमार यादव, पैरालीगल वॉलिंटियर्स शिव शंकर सिंह और सुनील कुमार गौतम, गुलाम अब्बास जैदी, विद्यालय परिवार के लोग और संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। अंत में प्रधानाचार्य के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैंरू जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग जौनपुर की ओर से शिया इंटर कॉलेज के मैदान में दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे, अभिभावक एवं शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया एवं विनीत सेठ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने की। अतिथिगण ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल एवं जिला समन्वयक समेकित शिक्षा शशिधर उपाध्याय ने अतिथियों का स्वागत किया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने मशाल दौड़ कराकर खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसके उपरांत दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने सराहा। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण ने विभिन्न प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल, प्रमाण पत्र, ट्रैक सूट, प्लेट एवं टॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। बच्चों का उत्साह देखकर उपस्थित जनसमूह ने तालियों से उनका मनोबल बढ़ाया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने दिव्यांग बच्चों एवं अभिभावकों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को दिव्यांग न समझें बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आज का समय अवसरों से भरा है और दिव्यांग बच्चे भी समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल कर रहे हैं। कार्यक्रम में आलोक कुमार गुप्ता, आकिंचन संस्था की रेखा त्रिपाठी, रेखा सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अश्वनी सिंह, सुभाष गुप्ता, डीसी एमडीएम अरुण मौर्य, डीसी प्रशिक्षण विशाल उपाध्याय, एसआरजी अजय मौर्य, कमलेश यादव, डॉ. पी.डी. तिवारी सहित बड़ी संख्या में विशेष शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद यादव के पिता का 88 साल की उम्र निधन,शोक की लहर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद यादव के पिता का 88 साल की उम्र में लखनऊ के मेदांता में उपचार के दौरान निधन हो गया। जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव कि अचानक तबियत एक सप्ताह पूर्व खराब हुई थी। जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां उपचार चल रहा था, लेकिन अचानक मंगलवार की शाम करीब सात बजे उनका निधन हो गया। निधन की खबर लगते ही उनके पैतृक ग्राम पनियरिया समेत पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गईलोगों ने घर पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किया। बता दें कि सवधू यादव जनप्रिय व समाज सेवा से जुड़े थे।इनका अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर राम घाट पर किया गया।इस दौरान हजारों लोगों ने घाट पर पहुंचकर शोक संवेदन व्यक्त किया।

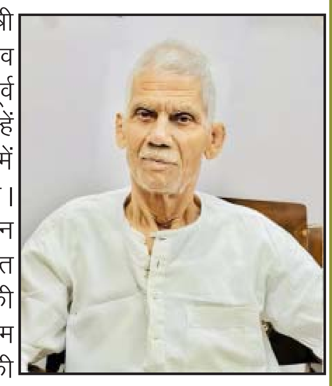

विश्व दिव्यांगता दिवस पर कई बच्चे हुए पुरस्कृत

अयोध्या। बुधवार को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर बचपन डे केयर सेण्टर जोगीतारा जनौरा अयोध्या में श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, बौद्धिक अक्षमता के बच्चों द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।इस मौके पर इन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल–कूद प्रतियोगिता दौड़, मेढक दौड़, म्यूजिकल चेयर, रस्साकस्सी, छूकर पहचानों, क्रिकेट,

सुलेख, गुब्बारा, फोड़ना, बाल्टी में गेंद डालना, चित्रकला प्रतियोगिता,बैलेंसिंग प्रतियोगिता मे प्रतिभाग किया।जिसमें प्रतिभाग करने वाले बच्चों को कार्यालय के कनिष्ठ सहायक एवं बचपन डे केयर सेण्टर के समन्वयक, विशेष शिक्षक व कर्मचारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

महिला पुलिस के प्रयास से आपस मे रहने को तैयार हुए पति पत्नी

अयोध्या।बुधवार को महिला थाना पुलिस की सूझबूझ से पति–पत्नी शादी के काफी समय बाद एक बार फिर आपस में रहने के लिए एक दूसरे से सुलह समझौता महिला थाना परिसर में किया। इस संबंध में महिला थाना अध्यक्ष आशा शुक्ला ने बताया कि अरीबा फातिमा पुत्री इमदादुल्लाह निवासिनी बैरिया टोला थाना रौनाही जिला अयोध्या की शादी वर्ष 2022 मे सैफ अली निवासी जेपी कॉलोनी जल महल ब्रह्मपुरी जयपुर त्रिपोलिया बाजार राजस्थान के साथ हुई थी। जिनके बीच किसी कहा सुनी को लेकर दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। बताया कि इन दंपतियों के पास डेढ वर्ष का एक बच्चा भी है।उन्होंने बताया कि काफी प्रयास के बाद बुधवार को पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हुए। और आपस में रहने के लिए थाना परिसर में सुलह समझौता भी किया। इस मौके पर महिला उप निरीक्षक चेतना पांडे,महिला आरक्षी पायल सरोज, महिला आरक्षी साक्षी शुक्ला मौजूद रहे।

श्री नमो नारायण जनता मंदिर हजरतगंज में भव्य भंडारे का आयोजन

सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय

लखनऊ। श्री नमो नारायण जनता मंदिर हजरतगंज में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री श्री 1008 बाबा विभूति गिरी महाराज की समाधि पर आचार्य एवं भक्तों ने पुष्पांजलि अर्पित की तथा आशीर्वाद लिया। युवा सेवा समिति के वालंटियर सेवा भाव से कार्यक्रम संपन्न कराने में लगे रहे। इस अवसर पर सर्वश्री संत प्रसाद पांडे,संतोष कुमार पांडे, राजकुमार मिश्रा, विजय मिश्रा, विजय प्रकाश पांडे, राम कुबेर पांडे, पंडित हरि शरण दुबे, युवा सेवा समिति के अध्यक्ष गंगा अमर नानी, चिरंजी लाल, श्याम सुंदर, रंजीत सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।